

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 232) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना 14 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(दर0)—16—08/2010/122—श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पिश्चमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता बिना पूर्वानुमित के मुख्यालय से अनुपिश्यित रहना, उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सी0 डी० संरचना का क्षितिग्रस्त होना इत्यादि प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0—1029 दिनांक 16.8.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1100 दिनांक 29.8.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किए गये:—

- (1) काकराघाटी शाखा नहर के वि०दू० 68.20 निर्मित सी०डी० के अप० स्ट्रीम का दांया बैंक दिनांक 07.07.10 को क्षितग्रस्त हुआ। अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा दिनांक 08.07.10 को उक्त स्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर सात दिनों से रिसाव हो रहा था जिसकी मरम्मती स—समय नहीं किये जाने के कारण उक्त वि० दू० पर 30 फीट में नहर क्षितग्रस्त हो गया। मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के पत्रांक 2056 दिनांक 09.07.07 के द्वारा स्थल पर कैम्प कर युद्व स्तर पर टूटान की मरम्मित कराते हुए संरचना को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया परन्तु आपके द्वारा लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप सी० डी० संरचना का डाउन स्ट्रीम का दाया विंग वाल एवं रिटर्न वाल पूर्णतः क्षितग्रस्त हो गया जो आपकी कर्तव्य के प्रति लापरवाही उदासीनता एवं निदेश की अवहेलना का द्योतक है। जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है।
- (2) नीलामी सूचना सं0–01/2009–10 के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 4 तक की गयी नीलामी में नियमावली से हटकर नीलामी की गयी जो हेराफेरी कर राजस्व गबन करने का मामला है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के द्वारा आपसे दिनांक 21.4.10 को स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया जिससे उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों में आपकी संलिप्ता प्रमाणित होती है, जिसके लिए आप दोषी है।
- (3) शीर्ष 4700 अन्तर्गत आकस्मिक मद में बिना उच्चाधिकारी के निदेश के रू0 तीन लाख के प्राक्कलन की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान कर राशि की निकासी की गयी एवं इस राशि का भुगतान बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत कराये ही मजदूरों को भुगतान किया गया एवं राशि का समायोजन भी कर लिया गया। इस प्रकार बिना उच्चाधिकारी के निदेश के स्वयं प्राक्कलन की स्वीकृति देना, राशि की निकासी करना, बिना सक्षम पदाधिकारी के श्रमशक्ति स्वीकृत

कराये भुगतान करना एवं किये गये भुगतान का समायोजन करना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी है।

- (4) बिना उच्चाधिकारियों की अनुमित एवं स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना एवं उनके द्वारा दिये निदेशों की अवहेलना करना।
- (ii) विभागीय कार्यवाही में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें जांच पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये गये। तदुपरान्त प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0—934 दिनांक 23.8.12 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः—
 - (1) निन्दन वर्ष 2010-11
 - (2) तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- (3) निलंबन अविधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अविध की गणना पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री रामजी राम द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया। पूनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में वही तथ्य उद्धित किया गया है जो विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया गया था। जिसकी समीक्षा पूर्व में की गयी एवं समीक्षोपरान्त सभी आरोप सं0–01 से 04 तक प्रमाणित पाया गया। पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य आरोपी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त के आलोक में श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व अधिसूचना सं0—934 दिनांक 23.8.12 द्वारा पारित दण्डादेश को यथवत रखते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

यह निर्णय श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।

> बिहार—राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 232-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in